नवोदय टाइम्स

नई दिल्ली

NAVODAYA TIMES, New Delhi

ABC से प्रमाणित 1,34,053 प्रतियां प्रतिदिन (औसतः जुलाई-दिसम्बर 2017)

मॉडल जूलिया को डेट कर रहे हैं अर्जेंटीना की टैनिस स्टार डेल पेत्रो 12

वीरवार, 20 सितम्बर, 2018 • तदनुसार 4 आश्विन, विक्रमी सम्वत 2075 | www.navodayatimes.in |

1700 एकड़ में बनेगी इलैक्ट्रॉनिक्स सिटी

- देश विदेश की नामचीन कम्पनियां लगाएगंगी यूनिट
- प्रोजेक्ट को तीन चरणों में किया जाएगा विकसित

ग्रेटर नोएडा, 19 सितम्बर (ब्यूरो): यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए इलैक्ट्रॉनिक्स सिटी बनाएगा। 1700 एकड़ क्षेत्र में बसाए जाने वाले एक विशेष जोन में देश विदेश की नामचीन कम्पनियां अपनी यूनिट स्थापित करेंगी। इस विशेष मैन्युफैक्च्युरिंग इलैक्ट्रॉक्स जोन में कम्पनियों को विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। एमईजेड का विकास तीन चरणों में किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए कई कम्पनियों ने रुचि दिखाई है। जल्द ही प्राधिकरण इसके लिए संभवत: दीपावली तक स्कीम लांच करेगा। प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार एमईजेड की स्थापना के बाद स्थानीय लोगों के लिए बड़ी मात्रा में रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे।

यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सीईओ डॉ अरुणवीर सिंह ने बताया कि जेवर एयरपोर्ट बनाए जाने की प्रबल संभावनाओं के बाद क्षेत्र में उद्योगपति बड़ी संख्या में पूंजीनिवेश के लिए तैयार हैं। इस दिशा में प्राधिकरण जेवर एयरपोर्ट के आसपास मैन्यूफैक्चरिंग इलैक्ट्रॉनिक्स जोन स्थापित करेगा। इस एमईजेड का क्षेत्र संभवत: सेक्टर 10, 11, 24 और 28 में फैला होगा। इस जोन को तीन चरणों में स्थापित किया जाएगा तथा प्रथम चरण में 100 एकड़, द्वितीय चरण में 600 एकड़ तथा तृतीय चरण में 1000 हजार एकड़ जमीन आवंटित की जाएगी। प्राधिकरण द्वारा लाई जाने वाली योजना के अन्तर्गत प्रथम व द्वितीय चरण को शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग इलैक्ट्रॉनिक्स जोन में स्थापित होने वाली कम्पनियों में मोबाइल, टीवी, एलईडी सहित सभी तरह के इलेक्ट्रानिक्स उत्पादों तैयार किए जाएंगे। एमईजेड में अपनी यूनिट स्थापित करने वाली कम्पनियों को अपने आवेदन के साथ डीपीआर भी पेश करनी होगी। भूखण्ड़ आवंटन के लिए कम्पनी को कुल कीमत का 10 प्रतिशत जमा करना होगा। भूखण्ड़ आवंटन करने से पूर्व पेश की गई डीपीआर रिपोर्ट का अध्ययन किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में 100 एकड़ जमीन पर प्राधिकरण का पूरी तरह से कब्जा है। द्वितीय चरण की 600 एकड़ जमीन का 55 प्रतिशत कब्जा प्राधिकरण ले चुका है। शेष जमीन पर कब्जा लेना बाकी है। तृतीय चरण की जमीन का प्राधिकरण अधिग्रहण करेगा।